



भारत की ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता, 2017

प्रलिस के ललल:

भारत की ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता, 2017, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA), वशिव ऊर्जा आउटलुक 2023, IEA के साथ रणनीतिक साझेदारी समझौता, IEA स्वच्छ कोयला केंद्र ।

मेन्स के ललल:

भारत की ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता, 2017, वभिन्न क्षेत्रों में विकास के ललल सरकारी नीतलल और हस्तक्षेप एवं नीतलनरलमाण तथा कार्यान्वयन से संबधतल मुददे ।

[स्रोत: इंडयलन एकसप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी \(IEA\)](#) ने अपनी रपलरट वशिव ऊर्जा आउटलुक 2023 में इस बात पर प्रकाश डाला है कल भारत की ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ECBC), 2017 इसे अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं से अलग करती है ।

- IEA ने कहा कल भारत विकासशील देशों में अद्वलतीय है क्योंकि व्यावसायकल इमारतों में ऊर्जा दक्षता के ललल इसके नयलम मज़बूत हैं, जबकल कई अन्य विकासशील देशों में इमारतों में ऊर्जा दक्षता भारत जतलनी उन्नत नहीं है ।

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी:

- अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी एक स्वायत्त अंतर-सरकारी संगठन है जसकल स्थापना वर्ष 1974 में पेरसल, फ्रांस में की गई थी ।
- IEA मुख्य रूप से अपनी ऊर्जा नीतलल पर ध्यान केंद्रतल करता है जसलमें आर्थकल विकास, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण शामिल है । इन नीतलल को IEA के 3 E के रूप में भी जाना जाता है ।
- भारत मार्च 2017 में IEA का सहयोगी सदस्य बना, लेकनल संगठन के साथ जुड़ने से बहुत पहले से ही यह IEA के साथ जुड़ा हुआ था ।
 - हाल ही में भारत ने वैश्वकल ऊर्जा सुरक्षा, स्थायतलव के साथ स्थरलता में सहयोग को मज़बूत करने के ललल [IEA के साथ एक रणनीतिक साझेदारी समझौता](#) कलया है ।
- वशिव ऊर्जा आउटलुक रपलरट IEA द्वारा प्रतवलरष जारी की जाती है ।
- [IEA स्वच्छ कोयला केंद्र](#) स्वतंत्र जानकारी और वशल्लेषण प्रदान करने के ललल समरपतल है कल कैसेकोयला, संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्यों के अनुरूप ऊर्जा का एक स्वच्छ स्रोत बन सकता है ।

भारत की ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ECBC), 2017:

- परचलल:
 - ECBC को पहली बार वर्ष 2007 में वदल्युत मंत्रालय के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) द्वारा जारी कलया गया था, इसके बाद वर्ष 2017 में इसे अदयतल कलया गया ।
 - वर्तमान में 23 राज्यों ने ECBC अनुपालन को लागू करने के ललल नयलमों को अधसूचतल कलया है, जबकल महाराष्ट्र और गुजरात जैसे बड़े राज्य अभी भी नयलमों का प्रारूप तैयार करने की प्रक्रलया में हैं ।
 - ECBC वाणज्यकल भवनों के ललल न्यूनतम ऊर्जा मानक नरुधारतल करती है, जसकल उददेश्य अनुपालन भवनों में 25 से 50% के बीच ऊर्जा बचत को सक्षम करना है ।
 - यह संहतल अस्पतालों, होटलों, स्कूलों, शॉपलिंग कॉम्प्लेक्स और मल्टीप्लेक्स जैसे व्यावसायकल इमारतों पर लागू होती है, जनकल

कनेक्टेड लोड 100 किलोवाट या उससे अधिक है या अनुबंध की मांग 120 kVA या उससे अधिक है।

■ उद्देश्य:

- भारत में ECBC भवन डिज़ाइन के **छह प्रमुख घटकों पर ध्यान केंद्रित** करता है, जिसमें आवरण (दीवारें, छत, खड़कियाँ), प्रकाश व्यवस्था, HVAC (हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग) सिस्टम एवं वदियुत ऊर्जा प्रणाली शामिल हैं।
- इन घटकों की **अनविर्य और नरिदेशात्मक दोनों आवश्यकताएँ** हैं। यह संहिता नए नरिमाणों तथा मौजूदा इमारतों की रेट्रोफिटिंग दोनों पर लागू होती है।
- **अनुपालन वाली इमारतों को दक्षता के आरोही क्रम में तीन टैगों** अर्थात् ECBC, ECBC प्लस और सुपर ECBC में से एक दिया जाता है।

■ ECBC की आवश्यकता:

- ECBC जैसे ऊर्जा दक्षता नरिमाण संहिता का कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण है क्योंकि भारत में इमारतों में कुल वदियुत खपत का 30% हिस्सा है, यह आँकड़ा वर्ष 2042 तक 50% तक पहुँचने की उम्मीद है।
- इसके अलावा BEE के अनुसार, अगले बीस वर्षों में मौजूदा 40% इमारतों का नरिमाण होना बाकी है, **जोनीत नरिमाताओं और बलिडरों को यह सुनिश्चित करने का एक बेहतर अवसर देता है कि ये संधारणीय तरीके से बनाई जाएँ।**

■ 2007 से 2017 तक की वकिस यात्रा:

- ECBC का वर्ष 2017 का अपडेट अतरिकित प्राथमिकताओं के संदर्भ में सूचित करता है, जैसे: नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण, अनुपालन में आसानी और नरिभिकर्य भवन डिज़ाइन रणनीतियों का समावेश।
- यह डिज़ाइनरों के लिये लचीलेपन पर भी ज़ोर देता है। यह वर्ष 2007 के संस्करण से एक महत्त्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है और संधारणीय तथा ऊर्जा-कुशल प्रथाओं की दशा में वैश्विक रुझानों के अनुरूप है।

ECBC के राज्य कार्यान्वयन की स्थितिक्या है?

- 28 राज्यों में से उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा केरल सहित केवल 15 राज्यों द्वारा नवीनतम 2017 (ECBC) नयिमां को अपनाया गया है।
- हालाँकि गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और मणिपुर ने अभी तक इन नयिमां को लागू नहीं किया है, जिससे संभावित ऊर्जा बचत नहीं हो पा रही है।
 - राष्ट्रीय अनुसंधान वकिस नगिम का अनुमान है कि स्वयं गुजरात ECBC के प्रभावी अनुपालन करके वर्ष 2030 तक 83 टेरावाट-घंटे ऊर्जा बचा सकता है।
- दूसरी ओर बिहार ने सबसे कम स्कोर किया तथा ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु व झारखंड को इमारतों में ऊर्जा दक्षता के मामले में पाँच सबसे नमिन राज्यों में शामिल किया।
 - **राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक (SEEI), 2022** में कर्नाटक राज्य को इमारतों में ऊर्जा दक्षता के लिये शीर्ष राज्य के रूप में स्थान दिया गया, इसके बाद तेलंगाना, हरियाणा, आंध्र प्रदेश एवं पंजाब का स्थान है।

ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिये सरकारी पहल:

■ PAT योजना:

- **परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम (PAT)** ऊर्जा बचत के प्रमाणीकरण के माध्यम से ऊर्जा गहन उद्योगों में ऊर्जा दक्षता में सुधार करने में लागत प्रभावी बढाने के लिये एक बाज़ार आधारित तंत्र है जिसका व्यापार में उपयोग किया जा सकता है।
- यह राष्ट्रीय उन्नत ऊर्जा दक्षता मशिन (NMEEE) का एक हिस्सा है, जो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (NAPCC) के तहत आठ मशिनों में से एक है।

■ मानक और अंकन:

- यह योजना वर्ष 2006 में शुरू की गई थी और वर्तमान में इसे संसाधनों/उपकरणों रूम एयर कंडीशनर, सीलिंग फैन, रंगीन टेलीविज़न, कंप्यूटर, डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर, वतिरण ट्रांसफार्मर, घरेलू गैस स्टोव, सामान्य प्रयोजन औद्योगिक मोटर, LED लैंप और कृषि पंपसेट आदि के लिये कार्यान्वित किया गया है।

■ मांग पक्ष प्रबंधन (DSM):

- DSM वदियुत मीटर की मांग या ग्राहक-पक्ष पर प्रभाव डालने के उद्देश्य से उपायों का चयन, योजना और कार्यान्वयन है।

आगे की राह

- IEA का मानना है कि भारत उन कुछ वकिसशील देशों में शामिल है, जिनके पास वाणजियिक और आवासीय इमारतों के लिये भवन संहिता हैं तथा इससे समान कार्यान्वयन क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण ऊर्जा की बचत हो सकती है।
- भारत ने **2022 में ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम** भी पारित किया, जो देश में बलिडगि संहिता के दायरे को और वसितारित करता है।
 - ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 अंतरनहिति कार्बन, शुद्ध शून्य उत्सर्जन, सामग्री और संसाधन दक्षता, स्वच्छ ऊर्जा की तैनाती एवं परपितर से संबंधित उपायों को शामिल करके ECBC को ऊर्जा संरक्षण एवं भवन संहिता में परिवर्तित करने का प्रावधान करता है।

